प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांकः 26 फरवरी, 2019**

विषयः- **मै0 ओरियोनेक्स फारमूलेशन प्रा0लि0, प्लाट नं0-ए-2/29 सेक्टर-15, गीडा, गोरखपुर को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु स्वीकृत अनुदान की द्वितीय एवं तृतीय किस्त हेतु एक मुस्त कुल धनराशि रू0-4.90 लाख (रूपया चार लाख नब्बे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0उ0नि0-2462/105/ब्याज उपादान/2018-19, दिनांक-14.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1/997/58-2-2013-10/12टी0सी0-1, दिनांक- 06.12.2013 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांकः 09.01.2018 एवं 15.02.2018 द्वारा **मै0 ओरियोनेक्स फारमूलेशन प्रा0लि0, प्लाट नं0-ए-2/29 सेक्टर-15, गीडा, गोरखपुर** को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु बैंक् द्वारा प्राप्त किये गये वास्तविक ब्याज के सापेक्ष नीति में प्राविधानित 07 प्रतिशत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या-56/2018/754/58-2-2018-300(5)/2018, दिनांक-21/05/2018 द्वारा धनराशि रू0-203.05 लाख तथा पुनर्वियोग के माध्यम से शासनादेश संख्या-02/2019/137/58-2-2019-300(15)/2017, दिनांक-12/02/2019 द्वारा धनराशि रू0-536.67 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध धनराशि (प्रस्तर-3) में से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में ब्याज के रूप में भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि के सापेक्ष उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के तहत अनुमन्य 07 प्रतिशत की दर से अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आकलित अनुमन्य ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु एक मुस्त कुल धनराशि **रू0-4.90 लाख (रूपया चार लाख नब्बे हजार मात्र)** को **द्वितीय एवं तृतीय किस्त** के रूप में प्रतिपूर्ति हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012-में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं अनुबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-65/58-2-2013-10/2012, दिनांक-21.01.2013 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाया।

(3) अनुदान हेतु स्वीकृत **द्वितीय एवं तृतीय** किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2012 के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्रयान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

(4) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2019 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(8) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्रयान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक, मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(9) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(10) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018, में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-16/2019/174(1)/58-2-2019, तद्दिनांक:

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) आयुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in